SHRI L. N. MISHRA: That impression of the hon. Member is not correct. The Ministry of Finance, as I think, need not be held responsible for the delay in sanctioning any expenditure for any project.

SHRI M. M. DHARIA: May I know from where the personnel required for these Technical Cells are recruited and whether the Government has made any arrangements for their training ? May we further know whether these Cells are likely to bring down the administrative expenses of the Government?

SHRI L. N. MISHRA : That is the idea. Efficiency and speed are the real objectives.

So far as the recruitment is concerned we are trying to have them from the various units and, if necessary, from outside also.

DR. M. M. S. SIDDHU : The hon. Minister sad that the difficulty has been the non-availability of experienced technical personnel. In view of the fact that bad planning is no better than no plann'ne, will the Minister have these Planning Cells only when adequate experienced personnel are available and not in a haste recruit persons who will do away with planning itself?

SHRI L. N. MISHRA : No, Sir. What the hon. Member says is not correct. I might say that we ave having these Cells to assist and augment the implementation of the Plan. We believe that the Cells that have been set up in the various Ministries have proved successful

SHRI ARJUN ARORA : May I know what type of experts the Government have in view for these Technical Cells ? Will they be experts in the work done by each Ministry separately or wiH th -v be omnibus experts who will go into the methods employed by the Ministry concerned in executing its work?

SHRI L. N. Mishra: No, Sir. is of different projects. Take the case of the Ministry of Industry or of the Department of Chemicals. They will have their own Cells for their purpose. The Ministry of Petroleum will have its own Cell for its purpose and it will be like that.

SHRI I. K. GUJRAL: Would the Minister recall that some time last year a decision was taken that in future after the Finance Ministry has budgeted, the Ministries concerned would be given complete freedom not to go to that Ministry again and again for sanctions and that they would have autonomy in d sposing of the money within the budget ceiling ? May I ask him if the Finance Ministry has since then conveyed this decision to the various Ministries ?o that the disposal of the work becomes more expeditious ?

SHRI L. N. MISHRA : I have answered a question on this point—I think in the Lok Sabha—and said that there was a Committee set up under the Chairmanship of the Cabinet Secretary; the Secretary (Expenditure) and perhaps the Secretary to the Prime Minister also were members. And I have given out what suggestions they have made and those suggestions are being implemented.

*554. *[The questioner (Shri Sitaram Jaipuria) was absent. For answer,* Vide *col.* 3325 infra.]

'जी' टाइप के सरकारी क्वार्टरों में पानी के मीटर

*555. श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री 18 नवम्बर, 1964, 5 मई तथा 8 सितम्बर, 1965 को राज्य सभा में क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 68, 87 तथा 564 के दिये गये उत्तरों को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माता सुन्दरी रोड तथा मीरदर्द रोड पर 'जी' टाइप क्वार्टरों में पानी के अलग अलग मीटर कब तक लग जायेंगे;

(ख) क्या यह सच है कि उस क्षेत्र में दूसरी मंजिल के क्वार्टरों में रहने वालों को पानी नहीं के बराबर मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनसे पानी के लिये वसूल किये जाने वाले नियमित मासिक प्रभारों की दर में परिवर्तन करने का कोई विचार है ?

tlWATER METERS IN *Xj'* TYPE GOVERNMENT QUARTERS

•555. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to ihe replies given to Unstarred Question Nos. 68, 87 and 564 in the Rajya Sabha on the lSih November, 1964, 5th May and 8th September, 1965 respectively and state :

(a) by whenseparate, water meters will ata Sundari Road and M

(b) whether it is a fact that the occupants of the second storey quarters in that area practically get no water; and

(c) if so, whether it is proposed to change the rate of regular monthly recovery on account of water charges from them ?]

निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बी० भगवती) : (क) इन क्वार्टरों में पानी के मीटर चैम्बरों को बाहर से हटा कर अन्दर लगा दिया गया है तथा दिल्ली नगर निगम को जमानत भी दे दी गयी है। आशा है कि नगर निगम जल्द ही मीटर लगा देगा।

(ख) जैसा कि 8 सितम्बर 1965 के सवाल नं० 564 के जवाब में कहा गया था कि नगर निगम के पानी के नलों में दवाब कम होने की वजह से गर्मी के मौसम में दिन में जब कि सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है, क्वार्टरों की पहली मंजिल पर पानी की सप्लाई कम पड़ जाती है। हालत तभी सुधर सकती है जबकि पानी के दबाव के साथ पानी की सप्लाई भी बढ़ जाय।

(ग) अलहदा मीटरों के लग जाने के बाद पानी का इस्तेमाल करने वाला जितना पानी वह इस्तेमाल करता है उस आधार पर पानी के बिल को सीधे दिल्ली नगर निगम में जमा करा देगा।

tfTHE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. BHAGAVATI): (a) Water meter chambers provided in these quarters have been shifted inside from outside and necessary security bonds for meters have been furnished to the Municipal Corporation of Delhi. It is expected that the Corporation will install the meters shortly.

(b) As stated in answer to Unstarred Question No. 564 on the 8th September, 1965, because of inadequate pressure in the Corporation's mains, water supply to first floor quarters is restricted, particularly during peak hours in the summer season. The position can improve only if the pressure is increased or supply augmented by the Delhi Municipal Corporation.

(c) After separate meters have been installed, the bills for water charges would be paid directly by the consumer to the Delhi Municipal Corporation on actual consumptions.]

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान् यह बतलायेंगे कि 5 मई, 1965 को जब प्रश्न का उत्तर दिया गया था तो उसमें यह बताया गया था कि मीटर एक या दो महीने में लग जायेंगे और वह एक दो महीने की जगह पर दस महीने के करीब होने को आ गये और अभी तक मीटर लगे नहीं, इसलिये

†[ ] English translation.

क्या अभी भी कोई निश्चित अवधि आप देने को तैयार हैं कि कितने महीने में मीटर लग जायेंगे और आज की तारीख से दो महीने में मीटर लग जायेंगे या नहीं ?

SHRI B. BHAGAVATI : Sir, the installation of these water chambers has been completed. Now it is for the Corporation to give the meters. It is expected that they will give the meters very shortly.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान् को यह ज्ञात है कि कारपोरेशन को अभी अधिक आमदनी हो रही है क्योंकि उन लोगों को कम पानी मिलता है और मीटर लगाने के बाद कारपोरेशन की आमदनी कम होगी और कर्मचारियों को लाभ होगा, इस लिये वे इस जल्दी में नहीं हैं कि वे मीटर लगावें और इस दृष्टि से क्या हमारी सरकार विचार करने को तैयार है कि वह कारपोरेशन को इस बात के लिये मजबूर करे कि एक महीने के अन्दर अन्दर वे मीटर लगायें अन्यथा उनके द्वारा जो निश्चित रकम ली जा रही है उसमें कमी की जाय ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी बड़ी अच्छी संस्था है और बड़ा अच्छा काम कर रही है। उनके मुताल्लिक यह कहना कि वे जानबूझ कर यह काम नहीं कर रहे हैं, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। पहले मीटर बाहर हुआ करते थे और चोरी हुआ करते थे और अब हमने अन्दर कर दिया और जमानत का पैसा भी दे दिया। जहां तक मेरा अपना जाती खयाल है इन लोगों को बड़ी जल्दी कनेक्शन मिल जायगा। माननीय सदस्य से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वे हमारे कर्मचारी हैं और उनके बारे में मुझे भी उतनी जल्दी है जितनी माननीय सदस्य को है।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : मंत्री महोदय के मत से कारपोरेशन बड़ा अच्छा है, एफिशियन्टली काम करता है और मंत्री महोदय ने कहा भी था कि दो महीने के अन्दर अन्दर मीटर लग जायेंगे और ऐसी अपेक्षा उनको थी, तो फिर बहुत जल्दी का मतलब कितने महीने से है ? एक तो यह प्रश्न हुआ और दूसरा प्रश्न यह है कि जो मीटर की जमानत का सौ सौ रुपया कर्मचारियों से लिया जा रहा है, तो जिस तरह से और जगहों पर जहां कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के क्वार्टर हैं, वहां सरकारी कर्मचारियों से कोई भी जमानत नहीं ली जाती है, उसी तरह से उन से भी कोई जमानत न ली जाय, इसके बारे में कोई निर्णय कर रहे हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जमानत तो हमें देनी पड़ेगी, उसको हम मना नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि हमारे कर्मचारियों से वह जमानत नहीं ली जा रही है बल्कि वह डिपार्टमेन्ट दे रहा है। मैं इसके मुताल्लिक तसदीक से नहीं कहता, लेकिन मेरे खयाल से ऐसा ही है।

SHRIMATI TARA RAMCHANDRA SATHE : May I know, Sir, *.i* there is any shortage of these meters ?

SHRI MEHR CHAND KHANNA : there used to be very heavy shortage of water and electricity meters. I do not know the position now. Whatever it is, there is very heavy shortage of meters in Delhi.

SHRI.I. K. GUJRAL: Is the hon'ble Minister aware that there is no shortage of meters and the real reason for the Corporaton not putting up meters in those quarters is that between his Ministry and the Corporation it has not yet been settled as to who would make the capital investment both in laying and buying the meters.

SHRI MEHR CHAND KHANNA: The information of the hon. Member, when he used to be the Vice-Chairman of the N.D.M.C, is a little out of date.